IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.8927 of 2023

==

Veena Kumari, wife of Indubhushan Sharma, Resident of Mohalla- Kasim Bazar, P.S.- Kasim Bazar, District- Munger.

... ... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Rural Development Department, Govt. of Bihar, Patna.
2. The District Magistrate, Patna.
3. The Deputy Development Commissioner, Patna.
4. The District Programme Officer, MGNREGA, Patna.
5. The Executive Engineer, MGNREGA, DRDA, Patna.

... ... Respondents

==

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Rakesh Kumar Sharma, Advocate Mr. Alok Anand, Advocate Mr. Piyush Kumar Pandey, Advocate
For the Respondent/s	:	Mr. Vikash Kumar, S.C.-11

==

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE SANDEEP KUMAR

C.A.V. JUDGMENT

Date : 09-01-2026

By way of this writ petition, the petitioner has prayed for the following reliefs:-

"i. *For issuance of writ in the nature of Certiorari for quashing the order dated 25.04.2023 passed by the Respondent No.1 and communicated to the petitioner vide Gyapank No.1728131 dated 27.04.2023 whereby and where-under appeal has been dismissed as well as the order dated 01.12.2022 passed by the District Magistrate, Patna (Respondent No.2) and communicated to the petitioner vide Gyapank No.2080 dated 01.12.2022 whereby and whereunder the contract of the petitioner on the post of Programme Officer, MGNREGA has been*

WEB COPY

cancelled and direction has been given for lodging of FIR.

ii. For issuance of writ in the nature of Mandamus for a direction to the respondent authorities to reinstate the petitioner on the post of Programme Officer, MGNREGA with all consequential benefits as the order passed by the respondent authorities is based on biasness and prejudice mind."

2. In the year 2007, the petitioner was appointed as the Programme Officer under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 and subsequently after working in various districts of Bihar, she was transferred and posted at Danapur Block, Patna vide order dated 18.12.2020, where she joined on 19.12.2020.

3. It is the case of the petitioner that while working at Danapur, the petitioner found that the *Panchyat Rojgar Sevak*, Ganghara, Danapur is not working properly and therefore the predecessor of the petitioner as well as the petitioner had sent several letters, bringing this to the notice of the respondent authorities. Certain *Van Poshaks* had also sent a letter to the respondent no.3 regarding the non-payment of their remuneration by the *Panchyat Rojgar Sevak,* Ganghara, Danapur. In this backdrop, a show cause notice was issued by the respondent no.3 on 02.09.2021 to the petitioner and others

WEB COPY

seeking an explanation regarding the non-payment of the remuneration to the *Van Poshaks.* In response thereto, the petitioner submitted her response on 24.09.2021, stating categorically, that all the schemes were initiated in the month of July, 2020, that is, before the joining of the present petitioner, and therefore the then Programme Officer and the *Panchyat Rojgar Sevak*, Ganghara were responsible for the non-payment. Further, upon learning of these facts, the petitioner has directed the *Panchyat Rojgar Sevak*, to make physical inspection of the schemes and submit a report to initiate the payments to the *Van Poshaks.* Subsequently, the payments were made, and the *Van Poshaks* as a consequence had sent an application dated 22.10.2021 regarding withdrawal of their earlier complaint.

4. It is the further case of the petitioner that suddenly a show cause notice dated 02.02.2022 was served upon the petitioner and others regarding the irregularities found in 17 plantation schemes during the inspection. In connection to the aforesaid show cause notice, the *Panchyat Rojgar Sevak*-Arun Kumar sent a letter dated 14.03.2022 to the petitioner, stating therein that there were certain defects in the records relating to the 17 plantation schemes which were removed and further that due to floods and ensuing water logging, some

WEB COPY

plants were destroyed, but were again planted and thereafter the remuneration would also be paid to the *Van Poshaks.* The petitioner sent her reply to the show-cause notice dated 02.02.2022 on 21.03.2022. Thereafter the respondent no.2, District Magistrate, Patna passed the order dated 01.07.2022, whereby, the contract of the petitioner to the post of Programme Officer, MGNREGA was cancelled and further an order of recovery of Rs.3,92,800/- from the petitioner was also passed. Aggrieved by the aforesaid order dated 01.07.2022, the petitioner preferred an appeal, raising the ground that the aforesaid order dated 01.07.2022 was passed without affording proper opportunity of hearing to the petitioner and further that the show cause notice did not contemplate the facts which were later on included in the order dated 01.07.2022. The appellate authority vide order dated 21.10.2022, remanded the matter back for a fresh consideration. Thereafter, the matter again came before the District Magistrate, Patna for re-consideration, and after affording an opportunity of personal hearing, the District Magistrate, Patna passed the impugned order dated 01.12.2022. Since the aforesaid impugned order brings out the background of the present case at hand, it may be apposite to quote the entire impugned order dated 01.12.2022, which reads as under:-

"श्रीमती वीणा कुमारी अनुबंध रद्द कार्यक्रम पदाधिकारी,

WEB COPY

प्रखण्ड–दानापुर जिला–पटना के मनरेगा योजना क्रियान्वयन में अनियमितता के आधार पर अनुबंध रद्द किये जाने तथा राशि वसूली से संबंधित मामले की पुनर्समीक्षा सुनवाई के दौरान की गई। (साक्ष्य स्वरूप सुनवाई के दौरान लिये गये फोटोग्राफ एवं उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न)

विदित है कि ग्रामीण विकास विभाग, **विहार** पटना के पत्रांक 11593 दिनांक 08.10.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक 01.12.2021 को जिला स्तरीय टीम (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं कार्यपालक अभियंता, मनरेगा) के द्वारा दानापुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत गंगहारा में मनरेगा अन्तर्गत वृक्षारोपण से संबंधित 17 योजनाओं की जाँच की गई। जांच के दौरान निम्नांकित मुख्य अनियमितताएँ पाई गई, जिस आधार पर कार्रवाई की गई–

आरोप–

1. वृक्षारोपण से संबंधित 17 योजनाओं (कुल व्यय की गई राशि 16,64750.00 रु०) बिना पूर्ण अभिलेख एवं पौधा लगाने हेतु EMR के बगेर सामग्री का भुगतान किया गया।

a. अभिलेख में योजना का उल्लेख आदेश फलक में नहीं है, जिससे यह तय कर पाना मुश्किल है कि योजना वार्षिक कार्य योजना में ली गई नहीं? इससे संबंधित कागजात अभिलेख में संलग्न नहीं है।

b. लाभार्थी का भूमि जिस पर पौधारोपण किया गया है से संबंधित कागजात एवं सहमति पत्र अभिलेख में संलग्न नहीं है।

c. अभिलेख ने पंचायत रोजगार सेवक के स्थान पर पंचायत तकनीकी सहायक का अभिकर्ता के रूप में बिना तिथि का हस्ताक्षर पाया गया।

d. पौधे लगाने हेतु मास्टर रॉल निर्गत नहीं किया गया है।

उपरोक्त मूल कागजात अभिलेख में नही होने के पश्चात भी कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।

2. कार्यस्थल पर निरीक्षण के समय 17 योजनाओं में से 16 योजनाओं में सूचनापट्ट नही पाया गया एवं अभिलेख में फोटोग्राफ भी नहीं माया गया। स्थल जाँच के उपरान्त स्पष्टीकरण पृच्छा में प्राप्त उत्तर में सूचनापट्ट के स्थान पर टीन प्लेट का सूचनापट्ट का फोटोग्राफ जमा किया गया जो मनरेगा अधिनियम के प्रतिकूल है क्योंकि विभागीय पत्रांक 346703 दिनांक 05.01.2018 के अनुसार टीन, लोहा एवं फ्लैक्स का सूचनापट्ट बनाना वर्जित है।

उल्लेखनीय है कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण योजनाओं में सूचनापट्ट के लिए निर्धारित राशि 2900/–रु० है जिसके स्थान पर 4500/–रु० का अभिश्रव संलग्न कर भुगतान किया गया है जो कि एक गंभीर वितीय अनियमिततां है। कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत तकनीकी सहायक के द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है।

3. सभी 17 योजनाओं में पौधा लगाने हेतु मास्टर रोल र्निगत नही किया गया है। अभिलेख में संलग्न वैजलिस्ट अवधी 10.06.2020 से 30.08.2022 कलु 82 दिन में मात्र एक मानव दिवस का भुगतान 194 किया गया ।

WEB COPY

मस्टर रॉल पर पंचायत रोजगार सेवक के स्थान पर पंचायत तकनिकी सहायक का अभिकर्ता के रूप में बिना तिथि का हस्ताक्षर पाया गया।

4. गैवियन (फैन्सिंग) एवं पेस्टीसाइड का कोई विस्तृत विवरण मापी पुस्त में दर्ज नहीं है फिर भी ।उवनदज को सनउचेनउ कर राशि की निकासी की गई।

a अभिलेख में संलग्न ठपसस टवनबीमते का संधारण त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया है तथा अभिश्रव बिना पारित हुए ही भुगतान की गई। इस आधार पर नियम संगत भुगतान की प्रक्रिया नही अपनायी गई।

b. मनरेगा नियम अन्तर्गत बड़े पौधे का मूल्य 35– रू० तथा छोटे पौधे का मूल्य 15–रू० निर्धारित है। लेकिन अभिलेख में विपत्र प्रति पौधे 25 रू० का संलग्न किया गया है।

5. निरीक्षण के समय योजनाओं में मात्र 01 से लेकर अधिकतम 101 पौधे जीवित पाये गए। क्रम सं० 13 की योजना में मात्र 01, क्रम सं० 08 एवं 12 की योजना में मात्र 02–02 क्रम सं० 06 की योजना में मात्र 03 पौधे जीवित पाये गए।

उक्त के संबंध में अभिकरण कार्यालय के पत्रांक 159 दिनांक 02.02. 2022 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की पृच्छा की गई :–

1. लाभार्थियों का भूमि से संबंधित कागजात एवं सहमति पत्र अभिलेख में संलग्न नहीं है।

2. अभिलेख एवं प्रतिवेदन में तत्कालीन पंक्रो०सं० श्री अखिलेश कुमार का हस्ताक्षर नहीं है। अभिलेख में प०रो० से० के हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान से नीचे एवं प्रतिवेदन में पं०री०से० के स्थान पर तत्कालीन पत०स० श्री संजीत कुमार का हस्ताक्षर चिना तिथि का है।

3. कार्य स्थल पर निरीक्षण के समय 17 योजनाओं में से कुल 16 योजनाओं में सूचनापट्ट नहीं पाया गया। अभिलेख में सूचनापट्ट का फोटोग्राफ भी संलग्त नहीं है। सूचनापट्ट के लिए प्राक्कलन में विभाग से निर्धारित राशि (2900.००रू०) से अधिक राशि का अभिश्रव संलग्न किया गया है।

4. योजनाओं में पौधा लगाने हेतु मस्टर रोल निर्गत्त नहीं किया गया है। तत्कालीन पं०ता०स० द्वारा मापी पुस्त में राशि दर्ज की गई है जो तत्कालीन कनीय अभियंता श्री प्रदीप कुमार द्वारा सत्यापित है। मापी पुस्त परः कार्यावधि /मस्टर रॉल एवं मापी लेने की तिथि भी अंकित नहीं है. जो मनरेगा अधिनियम के प्रतिकूल है।

5. गैबियन (फसिंग) एवं पेस्टीसाइड को बिना विस्तृत विवरण के ही पं०स०स० द्वारा मामी–पुस्त दर्ज किया गया है जो सही नहीं है।।

6. कुल 12 योजनाओं में 200 पौधों एवं वायर कॅसींग हेतु दो–दो अभिश्रय में राशि अंकित है।

7. निरीक्षण के समय योजनाओं में मात्र 1 से लेकर अधिकतम 101 पौधे जीवित पाये गए। क्रम सं० 13 की योजना में मात्र 01. क्रम स० 08 एवं 12 की योजना में मात्र 02–02 क्रम सं० 06 की योजना में मात्र 03 पौधे जीवित पाये गए।

8. कार्य स्थल का एक भी फोटोग्राफ अभिलेख में संलग्न नहीं है।

9. उपरोक्त सभी योजनाओं में अभिकर्ता पचायत रोजगार सेवक के स्थान पर किसी अन्य पंचायत रोजगार सेवक को प्रभार न देकर अनाधिकृत रूप से तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, श्री संजीत

WEB COPY

कुमार राय को बनाया गया है। इस संबंध में अभिलेख में कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर से कोई आदेश निर्गत नही है।

10. उपरोक्त सभी योजनाओं में सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता के सत्यापन के बिना राशि का भुगतान किया गया है।

श्रीमती वीणा कुमारी अनुबंद रद्द कार्यक्रम पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के उपरान्त विभागीय पत्राक 196 दिनांक 25:03.2022 में प्राप्त निदेश के आलोक में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, दानापुर की सुनवाई 28.05.2022 को जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष की गई। सुनवाई के दौरान तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी के पक्ष को सुनने के पश्चात दंड के साथ आदेश निर्मात किया गया । दिनांक 28.05.2022 को संपन्न सुनवाही के साक्ष्य के रूप में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी की उपस्थिति एवं उनसे प्राप्त लिखित प्रतिवेदन सलग्न है। इनके द्वारा विभागीय सुनवाई में वर्णित किया गया कि ''जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 878 दिनांक 20.05.2022 द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2022 को अपराहन 04:00 बजे उपस्थित होने का निदेश प्राप्त किंतु निर्धारित तिथि को सुनवाई में उपस्थित होने के बावजूद भी सुनवाई नही हुई।'' सुनवाई होने के बाद भी इस तरह का झूठा आरोप लगाना इनकी गलत मंशा, मिथ्या आरोप एवं उदंडता को दर्शाता है। कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1280 दिनांक 01.07.2022 के द्वारा तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुबंध को समाप्त करते हुए 3.928 लाख वसूली करने का निदेश पारित किया गया। इस आदेश ज्ञापांक में निम्नांकित 06 विन्दु उल्लेखित थें :–

1. संबंधित योजनाओं में पौधा लगाने के लिए म–डत निर्गत नही किया गया, सिर्फ एक दिन का मस्टर रॉल निर्गत कर योजनाओं को Ongoing कर उपस्थित दर्ज करते हुए सामग्री मद में कुल 16.37 लाख रू० का भुगतान किया गया। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

2. कुल 17 योजनाओं में 16 योजनाओं में सूचनापट्ट नहीं पाया गया। साथ ही निर्धारित राशि (2900/– रू०) से अधिक राशि (4500/– रू०) का अभिश्रव संलग्न कर राशि की गलत निकासी की गई है।

3. जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मापीपुस्त में मापी की तिथि एव योजनाओं की कार्यावधि अंकित नहीं पाई गई एवं पौधारोपण हेतु मस्टर रॉल निर्गत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कितने पौधे लगे थें अथवा पौधे लगाये ही नहीं गये थे। जॉच प्रतिवेदन में यह सत्यापित किया गया है कि सामग्री के विपत्र में निर्धारित दर से अधिक राशि अंकित कर राशि की निकासी की गई है। यथा छोटे पौधे के लिए 25/– रू० का विपत्र अभिलेख में संलग्न किया गया है, जबकि विभाग द्वारा निर्धारित दर 15/ रू० है।

4. जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित सभी योजनाओं में वनपोषकों की नियुक्ति नही की गई थी अथवा वनपोषको का भुगतान नही किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार नही किया गया है। स्थल पर पौधों की उत्तरजीविता न्यूनतम पाई गई।

WEB COPY

5. तत्कालीन कनीय अभियंता, मनरेगा द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित योजनाओं के अभिलेख में उनका हस्ताक्षर फर्जी है।

6. योजनाओं के संलग्न मूल अभिलेख में संबंधित लाभार्थियों का अनापत्ति प्रमाण पत्रध्भूमि दस्तावेज एवं कार्य स्थल का फोटोग्राफ जाँच के समय अभिलेख में नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के विरूद्ध अनुबंध रद्द कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा विभागीय स्तर पर अपील की गई, जिसकी सुनवाई दिनांक 11.10.2022 को विभाग द्वारा करते हुए अपने आदेश ज्ञापांक 1327721 दिनांक 25.10.2022 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा पुनः सुनवाई करने का निदेश दिया गया है। इस आदेश में विभाग द्वारा निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय है :–

"अपीलार्थी को किये गये स्पष्टीकरण में अंकित कारण पृच्छा के 10 बिन्दु में से जिला पदाधिकारी, पटना के अनुबंध रद्द संबंधी आदेश में जिन 06 बिन्दुओं को संदर्भित किया गया है, उनमें से कुछ बिन्दु कारण पृच्छा के बिन्दु प्रतीत नहीं होते हैं, इनकी पुर्नसमीक्षा किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।"

उक्त आलोक में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय है :–

a. अनुबंध रद्द संबंधी आदेश में कुल 06 बिन्दु है। इनमें कुल 04 बिन्दु क्रमांक 01, 02, 03 एवं 06 अपीलार्थी से की गई स्पष्टीकरण में उल्लेखित है।

b- अनुबंध रद्द संबंधी आदेश के क्रमांक 04 में न्पपोषकों की नियुक्ति नहीं किये जाने संबंधित तथ्य स्पष्टीकरण में स्पष्ट उल्लेखित नही है, परंतु स्पष्टीकरण में निरीक्षण के समय अतिन्यून संख्या में पौधों के जीवित पाये जाने का उल्लेख है साथ ही योजनाओं में पौधा लगाये जाने हेतु मस्टर रॉल निर्गत नही किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वनपोषकों की नियुक्ति एवं भुगतान की प्रक्रिया नही की गई थी, जो वृक्षारोपण योजना में शिथिलता एवं अनियमिता को दर्शाता है।

c- अनुबंध रद्द संबंधी आदेश के क्रमांक 05 में तत्कालीन कनीय अभियंता, मनरेगा द्वारा संबंधित योजनाओं के अभिलेख में उनके हस्ताक्षर फर्जी होने से संबंधित बिन्दु स्पष्टीकरण पृच्छा में शामिल नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण पृच्छा के उपरान्त कनीय अभियंता, मनरेगा द्वारा यह तथ्य प्रतिवेदित किया गया था।

पुनर्सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिसके आधार पर यह माना जाय कि सरकारी राशि के गबन में कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में उनकी संलिप्तता नही है। साथ ही विभाग में इनके द्वारा की गई अपील में दिनांक 28.05.2022 को निर्धारित तिथि को सुनवाई में उपस्थित होने के बावजूद भी सुनवाई नही होने का तथ्य एक मिथ्या आरोप एवं अपीलार्थी की धृष्ठता है।

उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी के विरूद्ध कार्रवाई के पूर्व विभागीय निदेश पत्रांक 196 दिनांक 25.03.2022 के आलोक में दिनांक 28.05.2022 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सुनवाई की गई थी। इस सुनवाई के दौरान उन्हे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया गया तथा उनके द्वारा आरोपों के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही

WEB COPY

किया गया था। (साक्ष्य के रूप में सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की उपस्थिति एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न)

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में अपीलार्थी के पूर्व का कार्यकाल भी प्रासंगिक है। यथा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के ज्ञापांक 160 दिनांक 24.01.2014 के द्वारा उन्हे सरकारी राशि के गबन करने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के आरोप में कार्यक्रम पदाधिकारी, छौड़ाही के पद से सेवामुक्त किया जा चुका है। साथ ही मनरेगा योजना के कार्यान्वियन में की गई अनियमितता के आधार पर अभिकरण कार्यालय बेगुसराय के आदेश ज्ञापांक 77 दिनांक 27.01.2021 से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगुसराय सदर के पत्रांक 42 दिनांक 31.01.2021 के द्वारा उनके विरूद्ध सिघौल थाना, बेगुसराय में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी की गई है। (छायाप्रति संलग्न)

पुनर्सुनवाई में मामले की सम्यक समीक्षा के उपरान्त अपीलार्थी के अपील को रद्द करते हुए पूर्व के अनुबंध रद्द एवं राशि वसूली का आदेश (ज्ञापांक 1280 दिनांक 01.07.2022) को यथावत रखते हुए घोर वित्तीय अनियमितता के आलोक में उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, दानापुर को निदेशित किया जाता है।

5. Being aggrieved by the aforesaid impugned order passed by the respondent no.2-District Magistrate, Patna, by which he had sustained the earlier cancellation of the contract of the petitioner under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 as the Programme Officer and order of recovery of Rs.3,92,800/- from the petitioner and additionally ordered for registration of F.I.R against the petitioner, the petitioner preferred an appeal which came to be rejected vide impugned order dated 06.12.2022.

6. The learned counsel for the petitioner has submitted that the impugned order dated 01.12.2022 passed by the respondent no.2-District Magistrate, Patna is bad and unsustainable since it has brought new points, beyond the

WEB COPY

charges levelled in the original show cause notice. The show cause notice issued to the petitioner was based on ten points, which according to the learned counsel for the petitioner, has not been taken into consideration in the aforesaid impugned order dated 01.12.2022 and rather the same has been passed on entirely new set of six points which do not form part of the show cause notice and as such are unsustainable. The learned counsel has emphasised that it is well settled that the punishment order can not be passed on new grounds which is not the part of the show cause notice since it violates the principles of natural justice. To buttress this argument, the learned counsel has drawn strength from the decisions of the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Commissioner of Income tax, Mumbai vs. Amitabh Bachchan*** reported as ***2016 (11) SCC 748*** and ***M/s Popcorn Entertainment and Ors vs. CT Industrial Corportaion and Ors.*** passed in ***Civil Appeal 941 of 2007***.

7. The learned counsel has also relied on the decision of the Division Bench of the Jharkhand High Court in the case of ***M/s C.J. DARCL Logistics Limited vs Union of India & Ors.*** reported as neutral citation ***2023 : JHHC : 4980-DB*** (W.P. (T) 215 of 2022).

8. It is next submitted on behalf of the

WEB COPY

petitioner that the detailed reply submitted by the petitioner was not considered by the respondent authorities before passing the impugned order dated 01.12.2022 and the fact that the respondent authorities have taken the past conduct of the petitioner into consideration while no such contemplation was made in the show cause is also violative of principles of natural justice.

9. The learned counsel has placed reliance on the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Md. Yunus Khan vs. State of U.P. & Ors.*** passed in ***(SLP (C) 19318 of 2007.***

10. It is also argued that impugned punishment order dated 01.12.2022 is cryptic and non-speaking in nature, therefore totally unsustainable and in the teeth of the decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Kranti Associates Pvt. Ltd. vs. Masood Ahmed Khan*** reported as ***(2010) 9 SCC 496***.

11. Lastly, it is also argued by the learned counsel for the petitioner that the respondent authorities have themselves not followed their own guidelines dated 08.07.2020 and as such, the impugned orders cannot be sustained.

12. A counter affidavit has been filed on behalf

WEB COPY

of the answering respondent nos. 2 to 4, wherein it is submitted that based on complaints received regarding implementation of the plantation work under the *Gram Panchyat,* Ganghara under the Danapur Block, Patna, a district level inspection team conducted enquiry / joint inspection on 01.12.2021 regarding the 17 schemes under MGNREGA. The aforesaid joint inspection comprised of District Programme Officer, DRDA, Patna and Executive Engineer MGNREGA Patna in presence of the Programme Officer, Danapur, *Panchyat Rojgar Sevak*, beneficiaries and the villagers. An inquiry report was submitted on 23.12.2021 noticing several irregularities in the execution of the plantation work.

13. Paragraph no.7 of the counter affidavit detailing the nature of irregularities found during inspection are as under:-

> *"7. That it has been found that the total amount of Rs. 16,64,750/- spent in the 17 schemes without verification of the complete records. The name of scheme has not been found to be mentioned in the records. The detail of the land/consent letter has not been found in the record on which plantation has been done. The signature of Panchayat Technical Assistant in place of Panchayat Rojgar Sevak has been found as executant and there is no date mentioned. The Master Roll has not been issued for plantations.*

WEB COPY

Out of 17 schemes 16 schemes has not been found to be listed on the notice board. There is no photograph of the plantation work done. On private land rate of Rs. 2900/- has been fixed for plantations schemes to be put on notice board. But for this Rs.4500/-has been paid, which is serious financial irregularity. This has been accepted by the concerned Programme Officer and Panchayat Technical Assistant. Further wire fencing of only four schemes has been done but payment for nine schemes has been done. There is no mention of fencing and pesticide work in the measurement book, but the amount has been withdrawn."

14. It is next submitted that a show cause was issued on 02.02.2022 to all concerned persons including the present petitioner and the petitioner was heard personally on 28.05.2022 before the District Magistrate, Patna and thereafter, impugned order dated 01.07.2022 was passed terminating the contract of the petitioner and ordering for recovery of Rs.3,92,800/- from the petitioner.

15. It is stated in the counter affidavit that after the remand by the appellate authority, the District Magistrate, Patna again heard the matter and during the reconsideration, the petitioner had appeared personally, but she could not bring any material/document which could prove her innocence in the

WEB COPY

alleged financial irregularity. During reconsideration, it was also found that earlier also, the District Magistrate, Begusarai had passed an order dated 24.01.2014 whereby serious charges of defalcation of Government money, dereliction of duty, carelessness and indiscipline were levelled against the petitioner. It was also submitted that vide letter dated 31.01.2021, the Programme Officer, Begusarai had even directed for registration of F.I.R.

16. Lastly, the learned counsel appearing for the respondents has supported the impugned orders under challenge and has submitted that the impugned orders do not suffer from any illegality and have been passed after giving proper opportunity to the petitioner.

17. I have considered the submissions of the parties and perused the materials available on record.

18. In the present case, based on the joint inspection report wherein several discrepancies were detected, a show-cause notice was issued to the petitioner on 02.02.2022. From perusal of the show-cause notice, it appears that the response from the petitioner was asked on ten points. However, the order dated 01.07.2022 indicates that altogether six points were considered, which according to the petitioner, were distinct

WEB COPY

and different from the ten points raised in the aforesaid show-cause notice issued to the petitioner. The aforesaid argument was made in appeal by the petitioner and on this ground, the appellate authority had remanded the matter back to the District Magistrate, Patna, for reconsideration. After remand, the District Magistrate, afforded personal hearing to the petitioner and passed the impugned order dated 01.12.2022, by which, the earlier punishment order dated 01.07.2022 was sustained and additionally, a direction for registration of the F.I.R. against the petitioner was passed. The aforesaid impugned order dated 01.12.2022 was challenged by the petitioner in appeal unsuccessfully.

19. From perusal of the impugned order dated 01.12.2022, it appears that though the petitioner was afforded an opportunity of personal hearing by the District Magistrate but the District Magistrate in the impugned order has recorded that the petitioner has failed to bring on record any document/material to establish her innocence, which inverts the burden on the petitioner which is impermissible.

20. It is trite law that the onus lies upon the department/authority concerned alleging misconduct against the delinquent, though strict principle of evidence does not apply

WEB COPY

but the threshold of preponderance of probabilities must be met by the department/authority based on relevant cogent materials. Mere submission of joint enquiry report does not end the work of the department but the aforesaid documents must not only be proved by the department, but the contents of the aforesaid report along with other relevant materials must illustrate the alleged act against the delinquent on the threshold of preponderance of probabilities. Moreover, the impugned order dated 01.12.2022 also records that the petitioner has an antecedent while she was posted in the district of Begusarai. This fact was neither mentioned in the show-cause notice nor a response was sought from the petitioner on this point.

21. This Court is of the considered opinion that the impugned order dated 01.12.2022 is not in compliance with the principles of natural justice and prejudice has been caused to the petitioner for non-observance of the principles of *audi alteram partem,* inasmuch as, the petitioner has not been afforded a meaningful opportunity to defend on the points on which the impugned order was passed.

22. In view of the aforesaid discussions, the impugned order dated 01.12.2022 passed by the District Magistrate, Patna and the consequential appellate order dated

WEB COPY

25.04.2023 are set aside. The matter is remanded back to the District Magistrate, Patna, who shall proceed from the stage of issuance of fresh show-cause notice to the petitioner, which shall contemplate proposed punishment together with the grounds on which the action against the petitioner is initiated, and thereafter pass a reasoned order in accordance with law after affording an opportunity of hearing to the petitioner.

23. With the aforesaid observations and directions, this writ petition is allowed to the above extent.

(Sandeep Kumar, J)

pawan/-

AFR/NAFR	N.A.F.R.
CAV DATE	14.10.2025
Uploading Date	09.01.2026
Transmission Date	

WEB COPY